सितंबर, 2019

आपदा संवाद

2019 की बाढ़ से निपटना

डीआरएम के लिए विज्ञान पर भारत–यूके कार्यशाला

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार, के कार्यालय ने यूके गो–साइंस के साथ दिनांक 29–30, अगस्त, 2019 तक नई दिल्ली में आपदा और आपातकालीन जोखिम प्रबंधन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। डॉ. पी.के. मिश्रा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य है, आपातकालीन स्थितियों और आपदाओं के प्रबंधन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए भारतीय तथा यूके के सलाह तंत्रों एवं अभ्यासों को साझा करना।

डॉ. पी.के. मिश्रा ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत और यूके को आपदा और आपातकालीन जोखिमों, जो देशों के जीवन और अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ता है, को समझने, कम करने और प्रबंधन करने के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षमताओं के अनुप्रयोग को इष्टतम बनाने के लिए साथ मिलकर काम करें।

प्रोफेसर के. विजय राघवन, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार ने कहा कि कार्यशाला में बातचीत का उद्देश्य नए अवसरों की पहचान कर तथा विज्ञान और तकनीकी पर विद्यमान भारत–यूके सहयोग पर निर्माण करके सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को अपनाने में सुविधायुक्त बनाना।

जाम्बिया के प्रतिनिधिमंडल का एनडीएमए का दौरा

एनडीएमए के अधिकारियों ने 22 अगस्त, 2019 को जाम्बिया गणराज्य के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकाल की। यह दौरा 20–22 अगस्त, 2019 तक उनके राजकीय दौरे का एक हिस्सा था।

बातचीत को मजबूत बनाने के लिए, एनडीएमए ने आपदाओं पर वैश्विक रुझान, भारत में डीआरआर के लिए संस्थागत तंत्र तथा प्राधिकरण के संचालन पर प्रस्तुतिकरण दी। प्रस्तुतिकरण में, जलवायु परिवर्तन का विशेष प्रभाव जिसके कारण भारत में गर्मी संबंधित मृत्यु दर में वृद्धि तथा देश में लू के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न तैयारी उपायों को भी शामिल किया गया है।

ज्ञान विनिमय तथा सर्वोत्तम प्रथाओं का साझा करना, जोखिमों को कम करने और कमजोर समुदायों को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बैठक में विचार–विमर्श से दोनों देशों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दिशा में उनके प्रयासों पर दोनों देशों को लाभान्वित करेगा।

एमआरडीएस प्रशिक्षण आयोजित

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सार्वजनिक स्थानों पर विकिरणकीय आपातकालीन स्थितियों के प्रबंधन पर पुलिस तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य चयनित अधिकारियों को व्यापक रूप से प्रशिक्षित करना है, जो इसके बाद इन आपातस्थितियों पर प्रतिक्रिया करने के लिए अपने संबंधित राज्यों में अन्य कार्मिकों को तैयार करेंगे। इस परियोजना के तहत, 56 चिह्नित शहरों के पुलिस विभागों में विकिरण उपकरणों को स्थापित किया जा रहा है।

19–31 अगस्त, 2019 तक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) के विशेषज्ञों द्वारा एनडीआरएफ के 6वीं बटालियन, वडोदरा, गुजरात में पुलिस कार्मिकों की 8वीं बेट्स को प्रशिक्षित किया गया।

19–31 अगस्त, 2019 को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) में विशेषज्ञ द्वारा प्रशिक्षण दिलाना

संग्रहालय और सांस्कृतिक विरासत पर बैठक

एनडीएमए ने 6 अगस्त, 2019 को संग्रहालय और सांस्कृतिक विरासत स्थलों से संबंधित आपदा जोखिम प्रबंधन (डीआरएम) मामलों पर प्रगति का जायजा लेने के लिए एक बैठक का आयोजन किया।

अगली पीढ़ी को ज्ञान एवं कौशलों को सौंपने के लिए हमारी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, हस्तलिपियों के संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय आधारित प्रशिक्षित जनशक्ति के सृजन के लिए, देशभर में नियमित आधार पर कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इन हस्तलिपियों के लिए राष्ट्रीय मिशन के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया था।

एनडीएमए ने यह सुझाव दिया कि, देश में बड़ी मात्रा में उपलब्ध हस्तलेखों को देखते हुए, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा हस्तलिपियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए कुशल प्रशिक्षकों का एक समूह तैयार किया जा सकता है। उसके बाद कुशल प्रशिक्षकों द्वारा हस्तलिपियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए सभी हितधारकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। देश में सभी हस्तलिपियों की मैपिंग के लिए एक योजना भी होनी चाहिए।

राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रतिनिधि ने कहा कि कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय ट्रस्ट (आईएनटीएसीएच) को संग्रहालयों की आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) की तैयारी का कार्य सौंपा गया है। इसकी तैयारी के लिए एक सांचा (टेम्पलेट) विकसित किया गया है। कार्य अक्तूबर, 2019 तक पूरा होने की संभावना है।

दूरसंचार इंफ्रा पर बैठक

हाल ही में हुई चक्रवात फोनी के प्रभाव के कारण भारत में, विशेषकर ओडिशा में आपदा तथा जलवायु समुत्थानशीलता दूरसंचार अवसंरचना तंत्र पर केंद्रित करने की आवश्यकता पड़ी।

16 अगस्त, 2019 को एनडीएमए ने ओडिशा में आपदा और जलवायु समुत्थानशील दूरसंचार अवसंरचना के निर्माण की ओर एक रोडमैप पर चर्चा एवं योजना बनाने तथा भारत के सभी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों तक विस्तार करते हुए ओडिशा में नीति विकसित करने में तथा दूरसंचार अवसंरचना के निर्माण एवं संचालन में शामिल हितधारकों को एक साथ लाने के लिए एक बैठक आयोजित की।

समुत्थानशील अवसंरचना आपदा की हानियों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।

वास्तविक समय पर बाढ़ चेतावनी के लिए टीएन स्मार्ट पर लॉग इन करें

टीएन स्मार्ट (विविध–खतरे संभावित प्रभाव मूल्यांकन तथा आपातकालीन मोचन ट्रेकिंग के लिए तमिलनाडु तंत्र) विविध खतरे जैसे–बाढ़, चक्रवात तथा सुनामी, बिजली आदि के लिए तैयारी, मोचन और प्रशमन उपायों को सुदृढ़ बनाने के लिए एक वेब–आधारित प्रणाली है, जो तमिलनाडु ने 26 अक्तूबर, 2018 को शुरू की थी।

यह तंत्र राजस्व प्रशासन विभाग तथा आपदा प्रबंधन, तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आरआईएमईएस क्षेत्रीय एकीकृत विविध–खतरे पूर्व चेतावनी तंत्र (आरआईएमईएस), थाईलैंड के सहयोग से एक वर्ष के रिकॉर्ड समय में संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

तंत्र के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक तथ्य यह है कि इसे ग्लोबल फ्रेमवर्क (सेंडाई फ्रेमवर्क, जलवायु सेवाओं तथा विकास लक्ष्य के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन का वैश्विक ढांचा) में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के साथ–साथ तमिलनाडु राज्य आपदा प्रबंधन परिप्रेक्ष्य योजना 2018–2030 के साथ संरेखित किया गया है।

टीएन–स्मार्ट का एक मोबाइल एप्लिकेशन भी है, जो सभी उपलब्ध बारिश स्टेशनों, वर्षा के आंकड़े, मौसम पूर्वानुमान तथा चिह्नित संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना का अवलोकन करने में उपयोग किया जा सकता है।

प्रमुख टीएन–स्मार्ट मॉड्यूल

यह एप्लिकेशन क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों को अलर्ट भेजता है और उसी पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई को ट्रैक करता है। नागरिकों द्वारा भी संकट भरे मेसेज भेज सकते हैं; जो उसके बाद कार्रवाई के लिए संबधित अधिकारियों को प्रेषित किए जाते हैं। इस मोबाइल एप्लिकेशन में एक अलार्म सिस्टम है, जो मोबाइल के साइलेंट मोड में भी अलार्म भेज सकता है।

इस तरह के कॉल (उपयोगकर्ता के स्थान, आपातकाल के प्रकार आदि) के अलग–अलग डेटाबेस, अतिसंवेदनशील समुदायों, आपदा क्षति तथा नाजुक अवसंरचना जैसे अस्पतालों, राहत केंद्रों आदि, नीति बनाने में सहायता करते हैं।

टीएन–स्मार्ट विभिन्न सीमाओं (थ्रेसहोल्ड) पर पहुंचने के लिए विश्लेषणात्मक डाटा का भी उपयोग करता है, जो बदले में विशिष्ट सलाहकारों तक पहुंचने में प्रयोग किए जाते हैं।

इस प्रकार, तंत्र नीति–निर्माताओं, परिचालन उपयोगकर्ताओं और साथ ही समुदायों को सहायता करती है। यह नीति निर्माताओं को आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्राथमिकता देनें में, प्रचालन उपयोगकर्ताओं को जोखिम पैटर्न को समझना, जोखिम वाले स्थलों, संवेदनशील जनसंख्या की पहचान करने और मोचन टीमों और सामग्रियों की तैनाती करने में मदद करती है। तंत्र समुदायों को पूर्व निकासी द्वारा जोखिम से बचाने में सहायता करते हुए सशक्त बनाती है, इस प्रकार समुत्थानशीलता में सुधार होता है।

यह एक वार्षिक कार्य निष्पादन लेखा–परीक्षण के लिए प्रदान करता है, जिसके आधार पर सतत रूप से सुधार हो। टीएन–स्मार्ट आपदा जोखिम न्यूनीकरण के सभी पहलुओं पर ट्रेकिंग, निगरानी, मूल्यांकन तथा प्रगति के रिकॉड (क्लोनिंग) के लिए एक 360 डिग्री समाधान है।

2019 की बाढ़ से निपटना

दक्षिण–पश्चिम मानसून को हिमालयी नदियों की घाटियों (बेसन) में बाढ़ लाने के लिए जाना जाता है। तथापि इस साल, इससे देश में 10 से अधिक राज्यों–दक्षिण में केरल से लेकर उत्तर में हिमाचल प्रदेश तक और पूरब में त्रिपुरा से लेकर पश्चिम में गुजरात तक, जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र में नहीं गिने जाते थे, में भी बाढ़ आई।

जैसे–जैसे मानसून का मौसम आगे बढ़ने लगा है, शीघ्र ही केंद्र सरकार बिना समय गवाएं, सभी बाढ़ प्रभावित राज्यों को समय पर हर संभव सहायता प्रदान करती है। पूर्व–चेतावनी एजेंसियों के पूर्वानुमान के आधार पर उपयुक्त जगह पर तैयारी उपाय किए गएं, संवेदनशील स्थानों पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल टीमों को व्यवस्थित किए गए तथा स्थिति को उच्चतम स्तर पर बारीकी से निगरानी की जा रही थी। वस्तुतः 13 जुलाई और 19 अगस्त, 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह जी द्वारा बाढ़ की स्थिति और विभिन्न हितधारकों की तैयारी की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता की। मंत्री जी ने 11 अगस्त, 2019 को कर्नाटक के बेलगावी जिला और महाराष्ट्र के सांगली और कोल्हापुर जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण (एरियल सर्वे) भी किया।

इसी बीच, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने स्थिति, तैयारी, बचाव तथा राहत कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए सभी हितधारकों के साथ नियमित बैठकें की।

सशस्त्र बल, एनडीआरएफ, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), तट रक्षक बल तथा केंद्रीय मंत्रालय के सभी हितधारक मंत्रालयों और विभागों ने बचाव और राहत कार्यों–लोगों को निचले इलाकों से निकालना, उन्हें राहत शिविरों (कैम्पों) में लाना, आवश्यकताओं को वितरित करना जैसे–भोजन के पैकेट, कपड़े, चादरें, कंबल, मोमबत्तियां, माचिस, मच्छर निरोधक, क्लोरीन की गोलियां, आवश्यक दवाएं, चिकित्सा शिविर लगाना आदि को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए साथ मिलकर काम किया।

गृह मंत्रालय ने राज्यों द्वारा किए गए नुकसान और राहत कार्यों का आकलन करने के लिए तथा अतिरिक्त निधियों के आवंटन के लिए अंतिम सिफारिश करने के लिए प्रभावित राज्यों का दौरा करने के लिए अंतर–मंत्रालयी केंद्र टीमों (आईएमसीटी) का गठन किया गया।

कुछ क्षेत्र अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य प्रशासन (मशीनरी) अपना काम कर रहा है। समय के भीतर यह ठीक हो जाएगा। हमें हमारे विकास लाभ को फिर से स्थापित करने में, पुनः प्राप्ति और निर्माण करने में सालों लगेंगे। पुनः घटित होने से बचने में हम सभी को भूमिका निभानी है। हमें अपनी छोटी सी भूमिका, बाढ़ से प्रभावित होने वाली जमीन पर निर्माण न करके, नालों में, कूड़ा–करकट प्लास्टिक बैग और बोटल्स न बिखर के तथा लोगों को भी ऐसा करने से रोकते हुए, निभा सकते हैं। क्या करें और क्या न करें का सरल सा सेट को अपनाने से हमें बाढ़–समुत्थानशील (सहनशील) बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। होशियार बनो। तैयार रहो।

श्री मंगेश घिल्डियाल, जिलाधिकारी , रुद्रप्रयाग. ऑन

जिला आपदा मोचन बल

रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र में आता है। इसकी भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए हैं, यह जिला भूस्खलन, बादल फटने और हिमानीय झील विस्फोट की बाढ़ के जोखिम का भी सामना करना पड़ता है। जिले केदारनाथ मंदिर सहित विभिन्न पर्यटक आकर्षण के लिए गौरवान्वित करते हैं और दुनिया भर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं। तेज और कुशल आपदा मोचन सुनिश्चित करने के लिए जिला में मार्च, 2018 को एक जिला आपदा मोचन बल का गठन किया। आपदा संवाद ने श्री मंगेश घिल्डियाल, जिला मजिस्ट्रेट, रुद्रप्रयाग के साथ बातचीत की, जिन्होंने इस बल को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

प्रश्न. यह बल (फोर्स) क्यों तैयार की गई थी?

उत्तर. रुद्रप्रयाग भूकंप, भूस्खलन, वन अग्नि और बादल फटने जैसे बहु–खतरों से प्रवण है। वर्ष 2013 में केदारनाथ में एक हिमनदीय झील विस्फोट हुआ, जिसके फलस्वरूप महत्वपूर्ण जान–माल की हानि हुई। जिला विभिन्न पर्यटकों और धार्मिक स्थानों के लिए भी घर है, जिसके फलस्वरूप साल भर पर्यटकों की बड़ी भीड़ होती है। वर्ष 2018 में केवल केदारनाथ में 7 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया। आपदा प्रबंधन हमारे लिए एक प्रमुख चुनौती है और इसका अच्छी तरह से सामना करने के लिए, हमने पिछले साल, मार्च में एक समर्पित आपदा मोचन बल की स्थापना की। यह देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है।

बल किसी भी आपातकालीन स्थिति में तत्काल और प्रभावी मोचन प्रदान करने के लिए है। एक और उद्देश्य, श्री केदारनाथ यात्रा के दौरान पर्यटकों, विशेषकर बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों का, की बड़ी संख्या में मौसमी प्रवेश का प्रबंध करना है।

वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा के समय, प्रशिक्षित जनशक्ति और समुदाय जागरूकता की आवश्यकता ज्यादा महसूस की गई। आपदा प्रबंधन पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों के सहयोग से कार्य कर रहा था।

इन लोगों को बार–बार प्रशिक्षित करना पड़ा क्योंकि वे न केवल प्रमुख कर्त्तव्यों पर केंद्रित रहना पड़ता है, बल्कि उन्हें नियमित आधार पर स्थानांतरण भी करते हैं। ऐसी कमी से प्रभावी ढंग से निपटने और हर समय जिला प्रशासन के निपटाने के समय एक समर्पित बल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, जिला आपदा मोचन बल का सृजन किया गया था।

प्रश्न. बल कितना मजबूत है? इसके कार्मिकों का चयन किस प्रकार किया गया?

उत्तर. वर्तमान में डीडीआरएफ में कुल 26 कार्मिक हैं। उनको प्रतिरक्षक दल (पीआरडी), जो युवा कल्याण विभाग द्वारा विकसित एक तंत्र है, से शॉर्टरिस्टेट किए गए हैं, जिसके माध्यम से वे स्थानीय स्वयंसेवकों, जो जब और जैसी आवश्यकता हो सेवाएं प्रदान करते हैं, और तद्नुसार भुगतान किया जाता है, का चयन करते हैं। युवा कल्याण विभाग के पास जिला वार्षिक योजना से इसका एक अलग बजट है और इस बजट से डीडीआरएफ टीम सदस्यों को एक निश्चित मासिक पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। अन्य संबद्ध व्यय, जैसे वर्दी, जूतें और उपकरण आपदा प्रबंधन के क्षमता निर्माण बजट से कवर किया जाता है। इन कार्मिकों को नियमित प्रशिक्षण भी दिलाए जाते हैं।

वास्तव में, इस मॉडल को आसानी से राज्य के अन्य जिलों में दोहराया जा सकता है।

प्रश्न. डीडीआरएफ कार्मिकों को किन कौशलों पर प्रशिक्षित किया गया?

उत्तर. शुरूआत करते हुए, डीडीआरएफ की टीम को खोज एवं बचाव, प्रथम उपचार, भीड़ प्रबंधन तथा अपातस्थिति मोचन पर एक माह का कठोर प्रशिक्षण कराया गया।

बाद में, टीम ने नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ माउन्टिनिरिंग (एनआईएम) उत्तरकाशी, एशिया में बेहतरीन माउन्टिनिरिंग संस्थानों में एक में एक 15 दिन का खोज एवं बचाव पाठ्यक्रम चालया। इसमें डीडीआरएफ टीम को हिमालय में, विशेषकर चट्टान, हिम और बर्फ, प्राथमिक, चिकित्सा, माउंटेन नेविगेशन, रेडियो टेलिफोनी, श्रव्य एवं दृश्य संचार सिगनल और रिक्तीकरण विधियों से संबंधित खोज एवं बचाव कार्यों को करने के लिए प्रशिक्षण किया गया।

डीडीआरएफ टीम सदस्यों को अपने कौशल अपग्रेड करने के लिए एनआईएम, उत्तरकाशी, से माउंटेनीरिंग तथा खोज एवं बचाव में एड्वांस कोर्स चरणों में है।

प्रश्न. अब तक समुदाय की प्रतिक्रिया कैसी रही?

उत्तर. स्थानीय समुदाय बहुत समर्थन करता है, क्योंकि वही लोग मोचन की गतिविधियों के प्राथमिक लाभार्थी हैं। डीडीआरएफ को मानसून अवधि के दौरान जिले के दूरस्थ और संवेदनशील स्थानों में तैनात करते हैं और गावों में विभिन्न घटनाएं जैसे–रोड बंद (ब्लॉकेज) भूस्खलन, सड़क दुर्घटना आदि में प्रथम मोचक के रूप में काम करते हैं।

जैसे ही कंट्रोल रूम को ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है, निकटतम डीडीआरएफ टीम से संपर्क किया जाता है, जो तत्काल प्रभावित स्थल की और चलती जाती है। जबकि एजेंसी मुख्य कार्य की जिम्मेदारी लेता है, डीडीआरएफ टीम संबद्ध गतिविधियां जैसे–ट्रैफिक का प्रबंधन करना, दुर्घटना के समय फंसे हुए लोगों को भोजन और पानी वितरित करने का प्रबंध करता है।

टीम ने श्री केदारनाथ वार्षिक यात्रा की शुरू होने से पहले 16 कि.मी. लंबी गौरीकुंड ट्रैक रूट को साफ करने में भी मदद की। यात्रा के दौरान, वे तीर्थयात्रियों की मदद करने के लिए विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं।

प्रश्न. कृपया कुछ विशिष्ट मामलों को साझा करें जहां यह बल लोगों के बचाव के लिए आया हो?

उत्तर. यद्यपि इस बल के गठन के बाद जिले में कोई बड़ी आपदा नहीं आई है, टीम ने विभिन्न दुर्घटनाओं तथा मानसून अवधि के दौरान कई लोगों का बचाव किया है।

हाल ही में, डीडीआरएफ की टीम ने 100 से भी अधिक पर्यटकों को सुरक्षित वापस लाए हैं, जो चोपता नाक एक गावं में फंसे हुए थे, जहां भारी बारिश की वजह से मीलों तक सड़कें बंद थी।

डीडीआरएफ टीम नियमित आधार पर स्कूल और गांवों में प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करती हैं। अब तक लगभग 2500 प्रतिभागियों को लाभान्वित करते हुए, 1700 से अधिक ऐसे प्रशिक्षण दिलाए जा चुके हैं।

१५वां स्थापना दिवस
15th Formation Day

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
National Disaster Management Authority

"अग्नि सुरक्षा"
"Fire Safety"

२७ सितंबर, २०१९
27 September, 2019

दि अशोक, नई दिल्ली
The Ashok, New Delhi

पता :
एनडीएमए भवन
ए–1, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली–110029
दूरभाष : 91.11.26701700
कंट्रोल रूम : 91.11.26701728
हेल्पलाइन नं० : 011.1078
फैक्स : 91.11.26701729

controlroom@ndma.gov.i[redacted] [redacted] apdasamvaad@gmail.com /NDMA.in @ndmaindia